+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(25 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- 'आधार' एवं अन्य बायोमेट्रिक तकनीक प्रणाली के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव: मूडीज
- केंद्र सरकार की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) योजना और उसका प्रदर्शन

'आधार' एवं अन्य बायोमेट्रिक तकनीक प्रणाली के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव: मूडीज

चर्चा में क्यों है?

- प्रमुख वैश्विक रेटिंग मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने **भारत के आधार कार्यक्रम जैसी केंद्रीकृत पहचान प्रणालियों** में **सामाजिक प्रभाव, सुरक्षा और गोपनीयता कमजोरियों के बारे में चिंता व्यक्त** की है।

- 23 सितंबर को जारी **"विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति"** पर एक रिपोर्ट में, मूडीज ने कहा कि अद्वितीय आईडी प्रणाली के परिणामस्वरूप अक्सर **"सेवा अस्वीकरण" होता है, और आर्द्र परिस्थितियों में बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग अविश्वसनीय हो जाता** है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

AADHAR या अद्वितीय आईडी प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है?

- उल्लेखनीय है कि आधार प्रणाली **फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन और वन-टाइम पास कोड (ओटीपी) जैसे विकल्पों के माध्यम** से **सत्यापन के साथ सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाती** है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा प्रबंधित **'आधार' का लक्ष्य हाशिए पर मौजूद समूहों को मुख्यधारा में एकीकृत करना और कल्याणकारी लाभों की पहुंच का विस्तार करना** है।
- **सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** के लिए सरकार द्वारा आधार को अपनाया जाता है।
- **उल्लेखनीय है कि यह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का एक प्रमुख उपकरण है। साथ ही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमुख अवयव** भी है।
- मूडीज ने **'आधार' को "दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आईडी कार्यक्रम" के रूप में स्वीकार किया**, जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का उपयोग करके 1.2 बिलियन से अधिक भारतीय निवासियों को अद्वितीय नंबर प्रदान करता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

बायोमेट्रिक तकनीक को लेकर मूडीज का प्रमुख निष्कर्ष:

- **आधार के कारण अक्सर सेवा से इनकार कर दिया जाता:**
  - ➢ मूडी के ने जोर देते हुए कहा कि 'आधार' का लक्ष्य हाशिए पर मौजूद समूहों को मुख्यधारा में एकीकृत करना और कल्याणकारी लाभों की पहुंच का विस्तार करना है।
  - ➢ लेकिन **इस प्रणाली के परिणामस्वरूप अक्सर सेवा से इनकार कर दिया जाता है,** और **विशेष रूप से गर्म, आर्द्र जलवायु में मैनुअल मजदूरों के लिए** बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता कम या संदिग्ध हो जाती है। उल्लेखनीय है कि **सरकारी कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विशेष रूप से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना** के तहत मजदूरों के लिए आधार-आधारित भुगतान को अनिवार्य करने के निर्देश के **मद्देनजर रेटिंग एजेंसी की टिप्पणियां महत्वपूर्ण हो जाती है।**
  - ➢ अगस्त में, **सरकार ने मनरेगा लाभार्थियों के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) पर स्विच करने की समय सीमा पांचवीं बार बढ़ा दी, इसे 31 दिसंबर, 2023** तक बढ़ा दिया।

- **गोपनीयता, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**

  ➢ रेटिंग एजेंसी ने **'आधार' और एक नए क्रिप्टो-आधारित डिजिटल पहचान टोकन जिसे 'वर्ल्डलाइन' कहा जाता है, को दुनिया में दो डिजिटल आईडी सिस्टम कहा है जो अपने पैमाने और नवाचार की सीमा के कारण खड़े** हैं।

  ➢ इस बात पर जोर देते हुए कि **'आधार' जैसी आईडी प्रणालियां विशिष्ट संस्थाओं के साथ संवेदनशील जानकारी की एकाग्रता का कारण बनती हैं और डेटा उल्लंघनों के जोखिम को बढ़ाती** हैं, **मूडीज ने ब्लॉकचेन क्षमताओं के आधार पर 'डिजिटल वॉलेट' जैसे विकेंद्रीकृत आईडी (DID) सिस्टम के लिए एक पिच बनाई है** जो उपयोगकर्ताओं को अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। **उनके निजी डेटा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम कर सकती है।**

- **विकेंद्रीकृत आईडी (DID) सिस्टम:**

  ➢ कैटेलोनिया, अज़रबैजान और एस्टोनिया में सफल कार्यक्रमों का हवाला देते हुए जिन्होंने **डिजिटल पहचान जारी करने के लिए ब्लॉकचेन-आधारित सिस्टम का उपयोग किया है,** का हवाला देते हुए एजेंसी ने कहा, "हाल के वर्षों में, **'आधार' जैसे केंद्रीकृत आईडी सिस्टम द्वारा उत्पन्न सुरक्षा और गोपनीयता कमजोरियों**

के लिए रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में ध्यान DID की ओर स्थानांतरित हो गया है।

- मूडीज ने बताया कि **DID को अपनाने से गोपनीयता बढ़ती है और बिचौलियों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी की मात्रा कम हो जाती है।**
- उल्लेखनीय है कि **DID में व्यक्तिगत डेटा उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में सहेजा जाता है और पहचान सत्यापन किसी एकल, केंद्रीकृत संस्थान के माध्यम से नहीं बल्कि ब्लॉकचेन जैसे विकेंद्रीकृत डिजिटल बहीखाता** पर होता है।

- **नकारात्मक सामाजिक प्रभाव:**
  - मूडीज ने माना कि **विकेंद्रीकृत आईडी भी कुछ चुनौतियां पेश करती** हैं।
  - व्यापक स्तर पर, **इसने चेतावनी दी कि डिजिटल आईडी, चाहे केंद्रीकृत हों या नहीं, नकारात्मक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि वे समूह की पहचान और राजनीतिक विभाजन को मजबूत कर सकते** हैं।

साभार: The Hindu

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

केंद्र सरकार की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) योजना और उसका प्रदर्शन:

क्या मामला है?

- द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) योजना के तहत स्वीकृत 70 परियोजनाओं में से केवल दो ही पूरी और चालू** है।

- APC योजना इस महीने की शुरुआत में खबरों में थी जब असम के सीएम की पत्नी से संबंधित कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने वाली इस योजना पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) योजना का प्रदर्शन:

- कुल **17 APC परियोजनाओं में मुख्य प्रसंस्करण और बुनियादी सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण पूरा कर लिया है**, लेकिन अभी तक **क्लस्टर में कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के संचालन की आवश्यकता को पूरा नहीं किया** है।
- कार्यान्वयनाधीन **शेष 51 परियोजनाओं में से 30 निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं।**
- **APC योजना कृषि मंत्रालय की मेगा फूड पार्क (MFP) योजना, का एक संशोधित संस्करण है, जिसे 2021 में बंद कर दिया गया** था क्योंकि यह अपने वांछित परिणाम "प्राप्त नहीं कर सकी"।
- 2020-21 में, **केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज ने मंत्रालय के लिए एमएफपी योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया** और ***"कई कमियों को उजागर किया और संकेत दिया कि योजना वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकी"***।
- कृषि मंत्रालय की **वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, कुल 79 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह संख्या अब घटकर 70 परियोजनाएं रह गई** है।

परियोजना में देरी होने का कारण क्या हैं?

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, **अधिकांश राज्यों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी की तारीख से 2 साल के भीतर पूरा करना आवश्यक है, पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, जिनकी समय सीमा 2.5 वर्ष से** अधिक है।
- इसके अतिरिक्त, **परियोजनाओं द्वारा 6 महीने का विस्तार मांगा जा सकता है, हालांकि इससे स्वीकृत सहायता अनुदान की कुल राशि में कमी आएगी। इस योजना में महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण विस्तार का भी प्रावधान** है।
- कृषि मंत्रालय के अनुसार, **संशोधित APC योजना में परियोजनाओं में देरी में -**
  - ➢ **भूमि उपयोग में बदलाव,**
  - ➢ **प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से मंजूरी,**
  - ➢ **ऋण देने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधि ऋण की मंजूरी और**
  - ➢ **कोविड से संबंधित देरी** - जैसी समय लेने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं।

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) योजना क्या है?

- इस योजना का उद्देश्य **उद्यमियों के समूह को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों/किसानों के**

समूहों को जोड़कर, क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं का विकास करना है।

- योजना के तहत प्रत्येक कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर में **दो बुनियादी घटक होते हैं यानी बुनियादी सक्षम बुनियादी ढांचा** (सड़कें, पानी की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति इत्यादि), **कोर इंफ्रास्ट्रक्चर / सामान्य सुविधाएं** (वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग आदि) और **न्यूनतम 25 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कम से कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ कार्यरत हों।**
- **एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए कम से कम 50 वर्षों के लिए खरीद या पट्टे पर कम से कम 10 एकड़ भूमि की व्यवस्था करना आवश्यक** है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां:

- **2015-16 और 2020-21 के बीच, भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने समग्र विनिर्माण क्षेत्र में 5.1% के विपरीत 10.3% की वृद्धि दर्ज** की।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- 2021 में जारी भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर केपीएमजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ***"विकसित अर्थव्यवस्थाओं और अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में, निर्यात में मूल्य वर्धित उत्पादों यानी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की भारत की हिस्सेदारी कम है"***।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक, **2016 से 2019 तक भारत के कुल खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी में कोई वृद्धि नहीं हुई और यह 31% पर स्थिर** रही। इसकी तुलना में, **2019 में चीन की हिस्सेदारी 52%, मेक्सिको की 50% और ब्राज़ील की 34%** थी।